>

Title: Need to link the import-export of agriculture produce with the crop cycle.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): माननीय सभापति महोदय, आज छः घंटे प्राइज राइस पर जो चर्चा हुई, उसी से जुड़ा हुआ मेरा जीरो ऑवर का विषय है। पिछले दो दशकों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन 18 गुना बढ़े हैं, लेकिन गेहूं और धान के समर्थन मूल्य मात्र 5 गुना बढ़े हैं। हालांकि इस दौरान खेती की लागत के दाम बढ़े, जिसके कारण उपज की लागत, उसकी बिक्री या कीमत के लगभग बराबर हो गयी है। केन्द्र सरकार को राज्य सरकारें लागत मूल्य का आंकलन करके भावी समर्थन मूल्य के लिए अपनी सिफारिशें भेजती है। लेकिन केन्द्रीय लागत मूल्य आयोग उन सिफारिशों को खास तवज्जो नहीं देता और स्वयं का आंकलन करके फसलों के समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है।

स्वामीनाथन आयोग लागत पर 5 प्रतिशत लाभांश की सिफारिश करता है फिर भी अमल के बाद किसानों को न्यूनतम मजदूरी मिल पायेगी। खेती के सभी इनपुट पूंजी पर निर्भर हो गये हैं। खेती की उपज लाभकारी बाजार में नहीं जुड़ पायेगी। अधिकांश फसलों की खरीद की व्यवस्था भी विफल रहती है। अधिक फसल आने पर दरें गिर जाती हैं तथा अधिक मात्रा में मंडियों में उपज पहुंचने पर भी दरें गिरती रहती हैं।

मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि उपरोक्त स्थिति के निवारण हेतु सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? मैं यह भी अनुरोध करना चाहती हूं कि फसलों के उत्पादन के आयात-निर्यात को फसल चक्र के साथ जोड़ा जाये। धन्यवाद।